निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश मित्र को करें और मजबूत : योगी

सीएम ने दिए निर्देश, ट्रेड लाइसेंस स्वीकृति की प्रक्रिया होगी और सरल

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी के निवेश मित्र, सिंगल विंडो आपरेटिंग सिस्टम को और प्रभावी व पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कई अन्य निर्देश भी दिए। कहा, इन्वेस्ट यूपी को और अधिक प्रभावशाली बनाने व अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश मित्र की सभी समस्याओं को दूर किया जाए।

सिंगल विंडो अधिनियम 2024 को प्रभावी तौर पर लागू करने के बाद अब इस माह से सिस्टम एग्रीगेटर की प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है, जिससे अलग-अलग विभागों के डाटा को एकत्र कर उनका एक ही स्थान पर निराकरण किया जा सके। अनावश्यक विलंब की स्थिती में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाई करने व वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे आनलाइन शिकायत करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इन्वेस्ट यूपी के तहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल)

लैंड यूज परिवर्तन प्रक्रिया का छह माह के भीतर डिजटलीकरण किया जा रहा है। भूजल उपयोग सहित बिजली व जल कनेक्शन की प्रक्रिया को भी तीन माह में पूरा किया जाएगा। सिंगल विंडो आपरेटिंग सिस्टम के तहत उद्योग को पर्यावरण मंजूरी व गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को तेज किए जाने व प्रदेश में औद्योगिक भूमि के लिए जीआइएस डाटा बैंक बनाने का निर्देश भी दिया गया।

खरीफ के लिए शत प्रतिशत ढैंचा हरी खाद का किया जाए प्रयोग : शाही: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा करते हुए खरीफ की फसल की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि खरीफ के लिए प्रदेश के सभी प्रक्षेत्रों पर शत-प्रतिशत ढैंचा हरी खाद का प्रयोग कर बोआई समय से पंक्ति में सुनिश्चित कराई जाए। क्षेत्र व कृषकों की मांग के अनुरूप नवीनतम विकसित प्रजातियों के ब्रीडर, आधारीय एवं प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। बीज उत्पादन के लिए नर्सरी, जुताई, रोपाई का तिथिवार कैलेंडर तैयार कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। खरीफ 2025 में अरहर की शत-प्रतिशत बोआई रिज मेकर से की जाए। सभी खंडों का मृदा परीक्षण अभियान चलाकर पूर्ण करें और उर्वरकों का प्रयोग मृदा नमूनों की जांच से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर किया जाए।

युवाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अब दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को नए कलेवर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चलाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर युवाओं को वैश्विक उद्योग के लिए तैयार करेगा। युवाओं को अच्छे मानदेय पर नौकरी मिले इस पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को दूसरे देशों में रोजगार मिले इसके लिए विभिन्न ट्रेड में दिए जा रहे प्रशिक्षण को अब जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।

उप्र कौशल विकास मिशन अब कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को उच्च मानदेय वाली नौकरियां दिलाने पर जोर दे रहा है। न्यूनतम 12 हजार रुपये मासिक मानदेय दिलाया जाएगा। न्यूनतम नौ हजार मासिक मानदेय मिल रहा है। इस महीने कार्यशालाओं का आयोजन कर परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ नि प्रशिक्षण प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाएगा।